Title : Regarding need to provide proportionate reservation to Backward Dalit Classes in Privatized Public Sector undertakings.

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : देश में निजीकरण बहुत तेजी से हो रहा है और जहां सरकारी उपक्रमों का निजीकरण् हो रहा है, वहां आरक्षण नीति भी धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है। यूपीए सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में सामाजिक आरक्षण लाने की बात कही थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

सभापति महोदय, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट मैडीकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही है। महिलाओं का आरक्षण भी विदिन दिकोटा, करने की बात चलाई जा रही है। इससे ऐसा लगता है कि यह भी ठंडे बस्ते में जाएगा। हमेशा सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, हमारे सारे रिजर्वेशन के मामले, धीरे-धीरे खत्म करते दिखाई दे रहे हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री महोदय से रिक्वैस्ट करता हूं कि समाज को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु जल्दी से जल्दी प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण की नीति लागू करनी चाहिए और डीनोटिफाइड नौमैडिक ट्राइब, जिनके ऊपर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से यही निवेदन है।